[Shri Lakshmana Mahapatro]

would have been given had we known that the Bill was to be taken up for consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): The Bill is listed for today. You cannot say that the Bill is not to be considered today. The Bill is on the List of Business. So that plea does not exist.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Tomorrow, Sir, Heavens will not fall if it is taken up tomorrow.

सदन के नेता (श्री लाल कृष्ण आडवानी): उपसभाध्यक्ष जी, यह सदन की इच्छा है क्योंकि इस सदन में दोनों परम्पराएं रही हैं कि इस प्रकार से जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के मोशन हैं कभी कभी वे बिना बहस के पारित हुए हैं और कभी कभी हमने काफी दिनों उस पर चर्चा की है, इस प्रकार के मोशन भी हैं। तो इसीलिए हमारी तरफ से, कोई हम आग्रह नहीं कर सकते, इन्सिस्ट नहीं कर सकते। यदि सदन की स्वीकृति होगी तो हो सकता है।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 242 AND 264 GIVEN ON THE 27TH JULY, 1978 REGARDING MANAGEMENT OF LARGE INDUSTRIAL HOUSES

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): All right. We now go to the Half-an-hour Discussion.

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आपका और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे उद्योग मन्त्री ने अनेक बार यह घोषणा की है कि इस देश में बड़े उद्योगपतियों को बहुत कुछ प्रोत्साहन मिला जो मोनोपोलिस्ट हाउसेज रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 10 साल में उनकी हस्ती दुगनी और चार गुनी हो गयी है। यह बहुत खुशी की बात है कि एकाधिकार के अन्तर्गत जितने भी बड़े हाउसेज हैं उनको तोड़ा जाये। हमारी जब कोशिश इस बात की है कि देश के अन्दर जो एकाधिकारी उद्योगपति हैं उन्हीं को तोड़ा जाये और जो विदेशी उद्योगपति है जो मल्टी नेशनल हैं और जो कि यहां से धन कमा कर विदेश ले जाना चाहते हैं। उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अभी हाल में उद्योग मन्त्री ने एक ब्लेड कम्पनी, शार्प ऐज कम्पनी है जिसमें 47 प्रतिशत हिन्दुस्तान लीवर का शेयर है और 43 प्रतिशत एसकार्ट का है, एसकार्ट भी लार्ज हाउस में है और हिन्दुस्तान लीवर की मानोपली हाउस है। हिन्दुस्तान लीवर का पैरेन्ट आर्गेनाइज़ेशन लन्दन में है।

मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि शार्प ऐज़ कम्पनी जिसका कि प्रोडक्शन जब वह रजिस्ट्रेशन के लिये था, उसके लिये सी० ओ० बी० की आवश्यकता नहीं थी। जब सी० ओ० बो० की आवश्यकता पड़ी तो जब उन्होंने दरख स्त दी तो तीन साल का हिसाब लगाना पड़ता है कि तीन साल के अन्तर्गत कितना उत्पादन उसका हुआ। उसका उत्पादन 132 मिलियन रहा। इन्होंने 200 मिलियन कहां से आर्डर दिया। जरा सोचा जाए। इतना ही नहीं, उसने यह भी कमिन्टमेंट किया था कि 45 प्रतिशत एक्सपोर्ट आबलीगेशन हम पर रहेगी। उसको घटा कर उसने 20 प्रतिशत कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि जो भी डिविडेन्ड होगा उसका दुगना एक्सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, अब इन्होंने 450 मिलियन का आर्डर दिया है। उस शार्प ऐज हाउस ने जो हिन्दुस्तान लीवर के अन्तर्गत है, 450 मिलियन का प्रोडक्शन है।

एक और ध्यान देने की बात है। ब्लेड का जो प्रोडक्शन होता है, उसका रा-मैटीरियल इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट ओरिएन्टिड यह इण्डस्ट्री है। इतना ही नहीं और भी मैं कहूंगा, ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उन्होंने लार्ज हाउस में

एसकार्ट कम्पनी है और एकार्डिंग टु ला इनके लिये बनाये हुए जो लार्ज हाउसिज़ हैं, उनको स्माल-स्केल के स्थान पर उद्योगों का लायसेन्स नहीं दिया जा सकता है ।

तीसरी बात यह है कि इस देश में जो स्थानीय उद्योगपति हैं उनकी लायसैन्सड कैपेसिटी आलरेडी तकरीबन 3600 मिलियन की है, 1250 मिलियन का आपका रिक्वायरमैंट है । इतना ही नहीं कर्नाटक गवर्नमेंट का एक पब्लिक सैक्टर था, मध्य प्रदेश का एक पब्लिक सैक्टर था, हिमाचल प्रदेश का एक पब्लिक सैक्टर था, इन लोगों ने भी विदेशी कम्पनी के कोआपरेशन में कोई कम्पनी फलोट करके इनके सामने प्रोडक्शन के लिये एप्रूवल के लिये दिया । इनको रिजैक्ट किया, अच्छा किया । मैं चाहता हू कि विदेशी कम्पनी को रिजैक्ट कर दिया जाए । मगर जिस कम्पनी के विदेशी हित हों और जो हिन्दुस्तान लीवर के अन्तर्गत हो, उस कम्पनी को इतना बड़ा प्रोत्साहन देने के पीछे बहुत गहरा सन्देह और ससपिशन उद्योग मन्त्री के ऊपर होता है ।

इसलिये उपसभाध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस कम्पनी पर पूर्व की सरकार ने फारेन ट्रेड के लिये एक टाइम-लिमिट दिया था जो 28 फरवरी को खत्म हो गया । फारेन ट्रेड मार्क जो कि शार्प ऐज कम्पनी का है इरास्मिक के नाम से । आप जानते हैं कि विदेशी कम्पनी के ट्रेड मार्क के पीछे इस देश में, दुख की बात है, आकर्षण रहता है कि इम्पोर्टिड चीज़ है । यद्यपि स्थानीय उत्पादन की चीज़ हो और उस पर विदेशी मार्क पड़ा हुआ हो । इसकी अखबार में भी बहुत चर्चा हुई है । इरास्मिक नाम से यह ट्रेड मार्क आया । उसकी कीमत स्थानीय ब्लेड जो कि 13-14 पैसे का मिलता है, उसके मुकाबले 32 पैसे का बिकता है और आज तक उस कम्पनी ने कोई एक्सपोर्ट नहीं किया । एक प्रश्न का जवाब उद्योग मन्त्री की तरफ से भी आया कि शार्प ऐज वालों की जो एक्सपोर्ट आबलीगेशन थी, उन्होंने वह पूरा नहीं किया ।

"The Chief Controller of Imports & Exports, who is concerned with the monitoring of export obligations, has informed that Messrs Sharp-Edge Limited have defaulted in the matter of fulfilment of export obligation stipulated by the Government while granting the foreign collaboration for the manufacture of Stainless Steel Safety Razor Blades. CCI&E has further informed that a show-cause notice has been issued to the firm and that their reply is awaited."

यह है 10 मई का उत्तर जो आपके सदन में आया है । इसके एक्सपोर्ट के अप्लीकेशन को नहीं माना और इसको उन्होंने 450 मिलियन का आडर दिया । यह हिन्दुस्तान लिवर्स के अन्तर्गत है । इन सारी बातों को .मैं सदन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हू ।

इतना ही नहीं हिन्दुस्तान लिवर्स कम्पनी को जो 450 मिलियन का आर्डर दिया उससे बात हुई थी--मालिक से । उन्होंने उनके पास एक खत लिख कर भेजा है :

"This is with reference to my talk in your office some time ago. On that occasion, you wanted the reference of the Sharp-Edge application for expansion to 450 million blades per annum. I am enclosing a copy of the application submitted to the SIA. I assure you that Sharp-Edge blades are of the highest quality and in great demand. As desired, we will try to break the monoply of 85 per cent or 95 per cent of production of blades being manufactured by one group of the company."

I do not know that group.

[श्री सीताराम केसरी]

इसके बाद उन्होंने आर्डर दिया । मैं इसलिए कहता हूं कि जार्ज फर्नान्डेज़ हमारे समाजवादी भाई हैं, उन्होंने विरोधी दल में रह कर बहुत सा पार्ट अदा किया है । इतना ही नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि हमारे दोस्त को जब जेल में थे उन्होंने मोरारजी देसाई को लिखा था कि चुनाव का बहिष्कार करो, जनतन्त्र का बहिष्कार करो, परन्तु मैं धन्यवाद देता हूं मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण को जिन्होंने चुनाव को एक्सेप्ट करके उन्हें मन्त्री बनाया । ये कहते हैं कि पूर्व की सरकार में बड़ी खामियां रही हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं यह फेवर क्यों दिखलाया गया ? दूसरे, कल भी "पैट्रियट" में न्यूज़ आई है कि उन्होंने एक अमरीकन कम्पनी को, जबकि इण्डो बर्मा कम्पनी ने सीमेंट कंटेनर के लिए आर्डर की बात की, तो उनके कैबिनेट मन्त्री के कहने पर भी इसी तरह का आर्डर किया है । इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इनके विभाग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और विदेशी कम्पनियों को तरजीह मिल रही है, छोटी छोटी कम्पनियों की बात छोड़िए ।

एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि शार्प-एज में 48 परसेन्ट फारेन का पैसा लगा हुआ है । इसके अलावा नान-रेजीडेंट भी है । इतना कह कर मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय इस पर अपनी सफाई दें और बताएं कि क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नेन्डीज) : उपसभाध्यक्ष जी, यह सही है कि शार्पएज नाम की एक कम्पनी है जिसमें हिन्दुस्तान लिवर्स की न 47 बल्कि सवा 47 फी सदी पूंजी है और इस्कोर्टस की 43 फी सदी । मगर यह सही नहीं है कि यह "फैरा" कानून के अन्तर्गत बैठता है. . .

श्री सीताराम केसरी : क्या ?

श्री जार्ज फर्नेण्डीज : यह सही नहीं है कि यह फेरा कानून के अन्दर बैठता है जिनकी इसमें सीधी विदेशी पूंजी नहीं लगी हुई है, क्योंकि कानून जो है उसमें जहां सीधी पूंजी लग जावे उसी को फेरा के अंतर्गत लिया जाता है . . .

श्री सीताराम केसरी : नहीं, समाजवादी जार्ज फर्नेन्डीज़ या भारत सरकार के मन्त्री ? दोनों में अन्तर आ गया है ।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैं सरकार का मंत्री बोल रहा हूं । यह भी सही है कि इसका उत्पादन 129 मिलियन ब्लेड से 137 मिलियन ब्लेड और 163 मिलियन ब्लेड, और उसके बाद 194 मिलियन ब्लेड रहा । मगर यह 1973 से लेकर 1977 तक । हमें कुछ ऐसा आभास हुआ जब हमारे मित्र सीताराम केसरी बोल रहे थे कि जैसे हम 1972 से यहां पर बैठ कर उनको कैपेसिटी बढ़ाने का लाइसेंस देने का काम कर रहे थे । यह लाइसेंस जिस के लिये बड़ी शिकायत हमारे मित्र केसरी जी कर रहे थे कि जो एक विदेशी कम्पनी को दिया गया वह 1973 में दिया गया । दरअसल उसके पहले से यह कम्पनी ब्लेड बनाती थी, लेकिन 1973 में एक विदेशी कम्पनी के साथ फ्रांस की तिबो कम्पनी के साथ, उसकी टेक्नोलाजी लेकर उनको ब्लेड बनाने की इजाजत दी गयी और जो देशी कम्पनी ब्लेड बनाती थी और हम उम्मीद करते हैं कि वह उस समय थी और देशी कम्पनी जिसकी बहुत फिक्र पड़ी है हमारे सीताराम केसरी जी को उस की कैपेसिटी उस समय भी थी । लेकिन वह कैपेसिटी रहने के बावजूद वह देशी कम्पनी देश में अपने ब्लेड बनाते रहने के बावजूद हिन्दुस्तान लीवर्स एण्ड स्कोर्टस वाली संयुक्त बनायी हुई कम्पनी को विदेशी कम्पनी के साथ मिल कर ब्लेड बनाने की, दो सौ मिलियन ब्लेड हर साल बनाने की इजाजत दी गयी और उस

को लाइसेंस देने का यह काम 1973 में हुआ। तो इसलिये मैं अपने मित्र को शिकायत को समझ नहीं पाया कि उन को हमारे बारे में क्या शिकायत है।

श्री सीताराम केसरी: आपने वह दिया।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : 1973 में हम कहां थे ? जिस सरकार ने उनको लाइसेंस दिया ह वह 1973 में दिया है। तो शिकायत हमारे बारे में क्या है ? यह दोनों कम्पनियां मिल कर एक नयी कम्पनी बनी शार्पेज . . .

श्री सीता राम केसरी 1973 में नहीं मिला। तीन साल का कोटा 1973, 1974 और 1975 का दो सौ मिलियन का दिया है। 1974 में 123 मिलियन था, 1975 में 132 मिलियन था और उसके बाद 1976 में . . .

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैं फीगर्स देता हूं। 1973–74 में शार्पेज का प्रोडक्शन था 129 मिलियन ब्लेड, 1974–75 में उसका प्रोडक्शन था 137 मिलियन ब्लेड और 1975 76 में वह हुआ 163 मिलियन ब्लेड और 1976–77 में वह हुआ 194 मिलियन ब्लेड। अगर मेरे मित्र का यह कहना है कि यह सारा जो प्रोडक्शन रहा वह बगैर इजाजत के हुआ . . .

SHRI SITARAM KESARI: It was under registration.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज: आप टेक्नीकैलिटीज में आ जाते हैं। यह टैक्निकल चीज नहीं है। यह कम्पनी 1973 से 1977 तक ब्लेड बनाती रहीं। रजिस्ट्रेशन के साथ उसने ब्लेड बनाये चाहे वह इजाजत उसने एक विदेशी कम्पनी को साथ लेकर ही ली। तो हमारे बन्धु का कहना यह है कि इस कम्पनी को ब्लेड बनाने की इजाजत 1973 में ही देने में आ गयी।

श्री सीताराम केसरी : दो मिलियन की इजाजत आपने 1977 में दी है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मेरे मित्र का अगर यह कहना हो कि सिर्फ दो मिलियन की देते और दो सौ मिलियन बनाते थे तो यह और ज्यादा गम्भीर मामला है कि दो मिलियन की जगह दो सौ मिलियन ब्लेड बनाते रहे।

(Interruptions)

श्री सीताराम केसरी : दो सौ मिलियन का सी० ओ० बी० आपने 1977 में दिया है।

SHRI GEORGE FERNANDES: I am only pointing out to my hon. friend that this company has been producing blades from 1973. In 1973 it produced 129 million blades.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): What was the licensed capacity?

SHRI GEORGE FERNANDES: Two hundred million blades. The COB licence was given when they got registered under the provisions of the MRTP Act. In March, 1975, they made an application for the COB licence, and, thereafter, the COB licence came into being. But this company was registered much earlier. Their foreign collaboration was approved in 1973. The company started producing blades from 1973. The company has been producing blades from 1973. Now, either I must be told that all this was illegal. What exactly is the complaint? What is the specific nature of the complaint? Either all this was illegal, the activities of this company were illegal or they were legal. This company started producing blades in 1973.

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat): He has made a specific point. He says the licence already granted in 1973.....

SHRI SITARAM KESRI: No. no. The licence has been granted in 1977—COB.

मेरा चार्ज यह है कि आप यह कह कर निकल जाना चाहते हैं कि पूर्व की सरकार ने उसको आर्डर किया। मैं कहता हूं कि प्रोडक्शन के लिए जो सी०ओ०बी० था बड़े-बड़े उद्योग

[Shri Sitaram Kesri]

यहां पर इतने बढ़ गये और आपने जो विदेशी फर्म थी उसका जो 135 मिलियन निकलता था उस पर आपने 200 मिलियन कर दिया। पूर्व की सरकार ने उसका टाइम टरमिनेट कर दिया तो आपने उसको दे दिया। आपने जो उसको फेवर शो किया इस परिस्थिति में नहीं करना चाहिये था।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : श्रीमन्, मैं समझ गया। लेकिन ये दोहरा रहे हैं कि 135 मिलियन को हमने 200 मिलियन किया, यह सही नहीं है। हम यह बता रहे हैं कि 1975-76 में इसका प्रोडक्शन 163 मिलियन ब्लेड था। 1976-77 में 194.30 मिलियन ब्लेड था। इसलिए जो सी०ओ०बी० लाइसेंस जो दिया कैरी-आन बिजिनेस लाइसेंस दिया उस आधार पर 1973 से 1977 तक आपने उनसे काम कराया। हमने उनको कानून के अन्तर्गत लाने का काम किया उनकी अर्जी पर तो उसमें शिकायत हमारे बारे में क्या है, यह मैं नहीं समझ पाता हूं।

उनकी दूसरी शिकायत यह है कि दो सौ हमने दिया था तुमने साढ़े चार सौ दिया है। सारी जो बहस हो रही है कि हमने उनको बढ़ावा दिया है, या हम उनको न बढ़ा रहे हैं, न हमने उनको बढ़ावा दिया है, न बढ़ा रहे हैं हां, उन्होंने अर्जी की। वे जो सम्बन्धित विभाग हैं, जो सम्बन्धित कमेटीज हैं उनके सामने पड़ी हैं।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, may I know from the hon. Minister . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please, you will have your chance.

SHRI K. K. MADHAVAN: . . . what exactly is the policy of the Government? Is it encouraging . . . (*Interruption*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): You reply to Mr. Kesri's points.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : हम एक स्पैसिफिक इश्यू पर बहस चला रहे हैं। जब वह हमारी सम्बन्धित कमेटी से मेरे पास आ जाएगा तब उस पर जो निर्णय लेने का काम है, उस पर उचित निर्णय हम करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Mr. Kulkarni, May I tell hon. Members that there are at least five speakers. Kindly put relevant questions only.

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): Only clarifications—with a speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): No speech. The Minister will reply in the end.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, fortunately the hon. Minister has got a better vocabulary and force by which he is pleading his case and my colleague, Mr. Sitaram Kesri, you know, is getting retorts. But there is some other point. I do not want to leave him at this—whether it was 1973 of 1977. I understand what you are talking. But the point is, you have all along been maintaining—"you" means your Government—that you would bar the intrusion of the multi-nationals in the industrial field in this country, particularly where your pet child of 500 reserved items in the small-scale sector is affected. Sir, I would like to say that this type of answer does not lead us anywhere. As a trade unionist for the last 30 years, he can shout very loudly. The point here is, we say that multi-nationals are given patronage by the Janata Government not on this very small issue of licence for blades only. Perhaps he may deny the licence of 400 million blades or whatever it is; he may. But the point is, I find that particularly the reservations made and the capacities reserved for the small-scale sector are being intruded into by the multi-national. And there I want your assistance. I am not challenging you. I know your *bona fides*. Your *bona fides*

are true. I am sure of it. Your integrity is there I want your assistance to protect the small scale industry. I only mention two or three items and ask you how far you stand in that respect. Menthol is being manufactured by the small scale sector. There are 250 small scale manufacturers employing about 30,000 to 40,000 workers. I understand Palmolive Colgate company has been given a licence to manufacture certain items. Is it a fact? If it is a fact, under what socialist programme is that licence given to Palmolive Colgate?

SHRI KALYAN ROY: Under social democratic programme.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: That is the first question.

The second is about the paper conversion industry. It is entirely a small scale industry. You have now allowed one Saigal Papers with the help of a foreign manufacturer, a multinational, into this small scale industry, particularly to manufacture such conversion which was usually available for the small scale sector.

Then the parametro phenol is now being allowed to be manufactured by the Hindustan Organics. This is not a multinational. This is a public sector company. So the basic point which I and my colleagues want to bring out is that the small scale sector particularly has to be protected from the big houses and multinationals. The indigenous industry, whether big, small or medium, has to be protected from multinationals. For this purpose what are those basic steps which your Government has announced and has followed in practice? We hear so many things. Only two days back you said about the Tata thermal power station. I am not against giving that licence to them. When indigenousJ capacity is going to be developed and when the State sector is not coming forward, something has to be done. Power must be there. Without power we cannot work. So, I can understand that. But the basic point that remains in this country is this. If Mr. Fernandes wants to remain true to his salt and true to his ideals of trade unionism, I want to ask for a specific assurance from him. These multinationals and big houses, just like in Japan, America and other developed countries, should restrict themselves to marketing and using of sophisticated technology and ancillary production must go to the small scale sector, and they have to employ the assistance of the small scale sector. I want to know whether you will see to it or not.

Then, the wage goods industry, whatever it is, has to remain in the small scale sector. The Palmolive, toothpastes, etc. all these cosmetics, have to be banned, have to be stopped just as you have stopped the Coca Cola business, to see that all these items come into the small scale sector.

Lastly, I want to go into the fundamental, structural changes and tilt to the development of small scale sector. I have brought to your notice many a time that statutory protection to the small scale sector is a necessity, it is a long-standing issue, and it is the demand of the small scale industrialists of the country for the last fifteen years, but it has not been fulfilled so far. For your information, Mr. Fernandes, just as in Emergency we demolished all the democratic institutions, you have stopped all small scale industries, boards and advisory committees. Now there is no forum for the small scale sector to have a dialogue with your Ministry. Therefore, please see, what best can be done by you.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Sir, the one point which I want to place before the Minister is that it is not very important as to when it started, whether it was there during the previous regime or at some other stage. My specific question to the Minister would be whether the policy that was being pursued by the previous Government in regard to multinationals will now

[Shri Sourendra Bhattacharjee]

continue. Will the multi-nationals and big industries be allowed to intrude into the fields of small-scale industries or diversify their production despite the restrictions placed on them by the Government? Or, does the Government envisage overhauling their policy in this regard? If so, within what time limit they propose to do it? We have been hearing from the Government that the matter is under consideration or the new policy is being formulated and that suitable steps will be taken in this regard. But side by side, in the name of continuation of the policy that has been in vogue new licences have been given and these multi-nationals are spreading their tentacles all over the country. The plea has been that you require something very urgently or there is indispensable necessity for something else. Every time there will be one plea or the other.

I do not want to enter into the question of the personal ideology of the hon. Minister. I only want to know whether the Government of India envisages a complete re-examination of their policies in this regard and overhauling them. We have been hearing the Ministers saying that we are following mixed economy in our country. Even this morning we heard this phrase. Does it mean that these multi-nationals or big industrial hoses will be allowed to expand their business, spread their tentacles and continue their practice of exploitation? Or, is any overhauling of the policy under contemplation? If so, when?

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन सवाल पूछ रहा हूं और इनके संबंध में किसी प्रकार की भूमिका नहीं बांध रहा हूं । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि फ्रांस की अर्थ व्यवस्था को दो सौ परिवार कंट्रोल करते हैं । अमेरिका के बारे में भी यही बात कही जाती है । भारत की अर्थ व्यवस्था को पिछले 30 सालों में 75 परिवारों ने कंट्रोल किया और उससे भी कम करके कहें तो 20 परिवारों ने कंट्रोल किया और अगर उससे भी कम करके कहें तो दो परिवारों ने कंट्रोल किया और अब भी ये लोग इस देश की अर्थ व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में मेरा पहला सवाल यह है कि क्या यह सही है कि बड़े औद्योगिक घरानों की पूंजी भारत के बाहर भी लगी हुई है ? यदि हां, तो कुल कितनी पूंजी विदेशों में लगी हुई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह किन घरानों की पूंजी है और बाहर के किन-किन देशों में लगी हुई है ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि आम तौर पर पूंजी बाहर तब जाती है जब देश के अन्दर रेट आफ प्रॉफिट कम होता है और डिक्लाइनिंग रेट आफ प्रोफिट होने के कारण इस प्रकार के औद्योगिक घराने अपनी पूंजी को बाहर के देशों में लगा देते हैं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में एवरेज रेट आफ प्रोफिट क्या है और विज-ए-विज दूसरे देशों में एवरेज रेट आफ प्रोफिट क्या है ? आखरी सवाल मेरा यह है कि क्या यह सही है कि नए औद्योगिक घरानों में वृद्धि पिछले 30 सालों में सब से अधिक हुई है और क्या यह बात भी सही है कि इन बड़े घरानों को बढ़ाने में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का हाथ था और क्या यह बात भी सही है कि इमरजेंसी के दौरान हमारे देश के बड़े घरानों के साथ श्रीमती गांधी का कोई गठबन्धन हुआ था ? इनके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उद्योग मंत्रालय कोई इस प्रकार की विस्तृत योजना बना रहा है जिसमें इन सब चीजों को बन्द किया जा सके यानी इन बुराइयों का सफाया करने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या आप इस योजना से इस सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Shri Kalp Nath Rai.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): I would like to know . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please co-operate. Shri Kalp Nath Rai will ask his question.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Is it not true that your policy in regard to MNCs. is one of open invitation?

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय ने अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी की घोषणा की है। उद्योग मंत्रालय में आने के बाद, चूंकि उनकी समाजवादी नीतियों में निष्ठा थी तो लोगों को आशा थी कि वे भारत की औद्योगिक नीति में कोई व्यापक परिवर्तन लाएंगे। आप जानते हैं कि पुरानी सरकार ने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और मल्टी नेशनल्स, इन तीनों के सहयोग से हिन्दुस्तान का आर्थिक और औद्योगिक विकास किया। लेकिन आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों कार्टर साहब ने सेन्ट्रल हाल में कहा था कि इतने कम दिनों में हिन्दुस्तान ने जो इंडस्ट्रियल जगत में तरक्की की और दुनियां का दसवां राष्ट्र बना, यह दुनियां के लिए एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। यह केवल कार्टर साहब ने नहीं कहा बल्कि दुनियां के जितने भी देश हैं उन्होंने इसे अक्सेप्ट किया है कि तीसरी दुनियां में हिन्दुस्तान ने जबर्दस्त इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट किया है जो बैलगाड़ी के युग से निकल कर अटामिक युग में पहुंच गया है। यह एक बड़ी घटना है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय उद्योग मंत्री जी से हमें आशा थी। पिछली सरकार ने प्राइवेट एकानोमी और पब्लिक एकानोमी या कुछ मल्टी नेशनल्स को हिन्दुस्तान में काम करने के लिए अलाऊ किया था। लेकिन उस सरकार का इम्फेसिस कहां था ? उसने पब्लिक सेक्टर एकानोमी को लगातार हिन्दुस्तान की एकानामी में प्रायरिटी, प्राथमिकता देते हुए देश में पब्लिक सेक्टर एकानामी को मजबूत किया था। प्राइवेट सेक्टर भी है इसमें दो राय नहीं, मल्टीनेशनल्स ने हिन्दुस्तान में काम किया, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर इन्टरेस्ट की . . .

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, how much time you have allowed to this Member?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Very short time only. He will finish soon if you allow him to finish.

श्री कल्प नाथ राय : लेकिन उद्योग मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि अगर चाहे भी तो समाजवाद की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि यदि वे ऐसा चाहें भी तो उसे एच० एम० पटेल लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि जनता सरकार के विचार टूटे हुए हैं, मन टूटा हुआ है। जनता सरकार दिशा हीन और नेतृत्व विहीन है। इसलिए यह सरकार कोई क्रान्तिकारी या समाजवादी कदम उठायेगी, मैं ऐसी आशा फर्नेन्डीज साहब से नहीं करता। वह ऐसा न कर सकते हों ऐसी बात नहीं, मगर आर० एस० एस० के साथ होकर यह नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि वह इसे नहीं कर पायेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें बुनियादी रूप से पूछना चाहता हूं जो कि मेरे जैसे आदमी के दिमाग को हमेशा डिस्टर्ब करती रहती हैं। जार्ज फर्नेन्डीज के नेतृत्व में, जो पब्लिक सेक्टर एकानामी पहले मजबूत हुई थी, वह और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए यह उनसे हमें आशा है। लेकिन अभी ब्लिट्ज में निकला है। इसमें झा साहब का फोटो है।

"BHEL sold to multinationals: NEW DELHI: By early next month, the Bharat Heavy Electricals Ltd. will be getting a new set of people. Shri Raghavan has been ousted by means of a well-planned conspiracy

[श्री कल्प नाथ राय]

.....Foreign lobbies, corrupt officials and politicians combined together have sabotaged....The BHEL has been sold out to the multinationals, they say."

जैसा यह कहते हैं मैं नहीं हूं। लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर "ब्लिटज" का सर्कुलेशन 10 लाख है और "ब्लिटज"ने मोराजी देसाई और चौधरी चरणसिंह के भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्रों को छाप कर सारे हिन्दुस्तान को कम से कम हिला तो दिया ही है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो कि हिन्दुस्तान की बुनियाद है, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स हिन्दुस्तान की इकानोमी की रीढ़ की हड्डी है, जिसको और मजबूत बनाने का काम आप को करना चाहिए, जिसका मैनेजमेंट चेकोस्लोवाकिया और रूस के कोलोब्रेशन से आज भी प्रगति कर रहा है, जिसका हाइयस्ट डेवलपमेंट रहा है, कभी उसकी कोई शिकायत नहीं रही उसका जर्मन सीमन्स के साथ कोलाबरेशन किया। क्या यह इस बात का अन्दाजा नहीं दिलाता है कि जिस तरह से मल्टीनेशनल्स ने चिली में जबर्दस्ती उलट पुलट कर वहां अलिदे की हत्या कराई, ये मल्टीनेशनल्स हिन्दुस्तान में भी इसी ढंग से .....

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री कल्प नाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह घटना घट रही है। इसमें पूरी सरकार का दबाव है । या व्यक्तिगत रूप से फर्नेन्डीज साहब का इसमें हाथ है । आखिर इस तरह से बातें क्यों निकल रही हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय मैं उन्हें जानता हूं, उनकी राष्ट्रीयता में मुझे पूरा विश्वास है लेकिन एक न्यूज निकली है—

Public Sector Unit Ignored—over Rs. 15 crores Contract to Multi-national".

लिखा है कि हिन्दुस्तान के पब्लिक सेक्टर की कम्पनी जो कम दाम में करोड़ों रुपये क कोटेशन पर सीमेंट की सप्लाई कर रही थी उसकी सप्लाई के लिए आर्डर एक मल्टीनेशनल को दिया गया । श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री उनके विरुद्ध थे लेकिन उनकी कम कोटेशन पर दिया गया । अगर प्राइवेट सेक्टर ...

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) किसको दिया गया ?

श्री कल्प नाथ राय : इंडस्ट्री मिनिस्टर जार्ज साहब कोई ऐसे नहीं है कि किसी बात को इशारे से न समझें ।

श्री सुरेन्द्र मोहन : शायद आपको याद नहीं है ।

श्री कल्प नाथ राय : हमें याद है। जार्ज फर्नेन्डीज साहब, मधु लिमये साहब, राजनारायण साहब के हाथ में हिन्दुस्तान की बागडोर होती तो मेरे जैसा आदमी आपके सहयोग में होता लेकिन जब आप चौधरी चरण सिंह जैसे जातिवादी, मोरारजी जैसा प्रतिक्रियावादी देश के घनघोर रिएक्शनरीज को जब आपने स्वीकार किया तो यह चीज मेरे से स्वीकार नहीं हो सकती । मैं लम्बी बहस ...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : लम्बी बहस मत छेड़िए ।

श्री कल्प नाथ राय : मैं समाजवादी लोगों का हमेशा लिहाज करता हूं । मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता उनके साथ ऐसा बनाएं जो चरण सिंह के साथ या मोरारजी के साथ है इस चीज का ध्यान रखें । इसलिए मेरे से छेड़छाड़ मत कीजिए, मैं यह चाहता हूं ।

प्राइवेट सेक्टर हिन्दुस्तान में 25–30 वर्षों से है । संविधान में लिखा हुआ है कि बड़े और छोटे पूंजी के दायरे (नेरो) होंगे लेकिन

इकानामी डिसटार्शन के नाते पूंजीपति घराने बढ़े हैं इसमें दो राय नहीं हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, कोर सेक्टर इकानामी हिन्दुस्तान में मजबूत हुई है चाहे मोमेंट का क्षेत्र हो, चाहे लोहे का क्षेत्र हो, चाहे हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़ का क्षेत्र हो, फर्टिलाइज़र का आयल या आयल एक्सपलोरेशन का क्षेत्र हो । मार्डन इकानामी के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उस थर्ड वर्ल्ड में हिन्दुस्तान का पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ है लेकिन कंज्यूमर गुड्स के कारखाने प्राइवेट सेक्टर में बढ़े हैं । पूंजीपति बढ़े हैं, डालमिया, टाटा, बिरला बढ़े हैं । मुझे खुशी होगी यदि देश की जनता . . .

SHRI K. K. MADHAVAN: You have given him more than 8 minutes; you had asked him to conclude within 3 minutes. I have watched.... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I have already asked him to conclude.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे झा साहब ने कहा कि 30 वर्षों में देश में एकाधिकार बढ़ा । यह सही बात है । यदि एकाधिकार न बढ़ा होता तो ट्रेज़री बेंचेज़ को छोड़ अपोज़ीशन बेंचेज में कांग्रेस न आती । गलतियों का फल कांग्रेस को भोगना पड़ा ।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): We can continue the discussion tomorrow and the day after tomorrow. We have come here since 10.30 A.M. Kindly have some mercy on us (*Interruptions*)

SHRI K. K. MADHAVAN: You are adopting double standards... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAMLAL YADAV): You are saying something unreasonable.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात हमें यह कहनी है कि अखबारों में इस बात का बड़ा हल्ला है कि आक्स-वेगन कम्पनी आटोमोबाइल इंडस्ट्री मल्टीनेशनल जो कि जर्मन की है उसकी हिन्दुस्तान में लगाये जाने की बात चल रही है । यह कहां तक सही है और । तीसरी बात यह कहनी है कि सेंट्रल प्राविसेज मैंगनीज़ ओर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में है जिसके ऊपर सरकार का करोड़ों रुपये का बकाया है । मगर जिस कम्पनी ने करोड़ों रुपया रिपैट्रीयेट करने के लिए सरकार को आवेदन पत्र दिया है, उनका क्लीयरेंस नहीं होना चाहिए जब तक कि वे टैक्स को न दें । यह मेरा चौथा निवेदन था ।

अब पांचवां निवेदन यह है कि 10 मई को शार्प एज कम्पनी के संबंध में आदरणीय इंडस्ट्री मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि जो एक्सपोर्ट आब्लीगेशन पूरा करना चाहिए था, वह पूरा नहीं किया है इसलिए उसको शो काज नोटिस दी गई है । तो जो नोटिस दी गई है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि जो नई सरकार के कम से कम समाजवादी उद्योग मंत्री हैं तो अगर वे चाहें तो भी प्राइवेट सेक्टर और मल्टी नेशनल कम्पनियों को नहीं हटा सकते हैं । क्योंकि उनकी सरकार पर चौदह आने एक से एक बदमाशों की पकड़ है । इसलिए वे चाहें भी तो इसको रोक नहीं सकते हैं । इसके अलावा एक निवेदन यह करना है कि जो पब्लिक सेक्टर की इकानामी जो भी मजबूत हुई है उसको वे मजबूत करें और हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल हाउसेज और मल्टी नेशनल से हिन्दुस्तान को बचाने की कृपा करें । इसके लिए पूरा देश उनका आभारी रहेगा ।

SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, normally I would not have liked to

[Shri K. V. Raghunatha Reddy]

intervene in this matter. While it is true that trans-national corporations—the correct word is 'trans-nationals'—are expanding the same policies, more or less, are being pursued or followed. Whether he has faith in those policies or not, I do not know. Nevertheless they are being pursued and giving place to the expansion of trans-national corporations or big business. I would only like to point out to my good friend, Mr. George Fernandes, that it may be of interest to him to study that in this country out of nearly 12000 to 15000 crores of rupees worth of investment made in the private sector by way of assets structure, the investment made by the private sector is of the order of Rs. 300 crores. With 300 crores of rupees, they are controlling the investment of 15000 crores of rupees. I would advise him not to go in for nationalisation, but to adopt different methodology for taking over the assets of the private sector by operating with the help of that can be available from financial institutions. L.I.C., etc. I was amased that with Mr. George Fernandes and other friends being in power in charge of vital sectors, even the clause relating to conversion of loans into equity has been removed in respect of Jute, Textile, Engineering and Sugar industries. The previous Government had inserted a definite caluse for converting loans into equity. Notwithstanding all the statements being made by the textile industry and the jute industry, the textile industry has made enormous profits from 1972-73 onwards. Even the jute industry has made not less than 48 per cent profit. In such cases, would the Minister not consider that even the economic growth of industrial production which he wants to achieve will not be possible in this country because the monopoly stage of economic development in relation to private sector has reached a stage of economics of anti-growth? Whatever may be the interest which the Government might take, structurally the economy cannot grow and the employment potential cannot grow unless there are programmes to deal with the mixed character of economy in the structural context. I would like him to apply his mind in this regard although what I have said may not arise exactly from the question that has been raised.

Sir, the Escorts Limited has been mentioned here. It has invested in other companies. And it would be of interest even to Mr. George Fernandes—I hope, he also knows it—that in the Escorts Limited, the public financial institutions have got nearly 45 per cent of the share. And if the loans given are converted or even the normal procedures are allowed under the Companies Act the Government could have easily taken over the Escorts Limited even long back. But, for the reasons best known to those who knew about them, this was not done.

SHRI GEORGE FERNANDES: I hope you are referring to yourself.

SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY: I know the reasons. But I am not instrumental in not taking over or otherwise. These are some of the aspects of the corporate sector. The mystery of inter-corporate finance, the mystery of investments of companies, the way in which they operate, all these will be of an interesting study if the hon. Minister would like to make a study, because there is a very facilitating methodology for taking over these companies instead of going in for nationalisation.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : एक मिनट का समय मैंने मांगा था। भाई कल्प नाथ ने स्वीकार कर लिया कि तीस वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने बड़े लोगों को उद्योग देकर देश को रसातल को भेज दिया और इसी का नतीजा हुआ कि आज वे आपोजीशन में बैठे हैं।

श्रीमन्, मेरा एक प्रश्न है उद्योग मंत्री जी से क्योंकि यह बहुत समझदार आदमी और हमारे मित्र भी है आज शासन पार्टी में आप उद्योग मंत्री हैं। मैं बनारस शहर की हालत की तरफ इनका ध्यान दिलाना चाहता हू कि जब गोल्ड कन्ट्रोल हुआ, उसी वक्त बनारस से साड़ी उद्योग मे जो धागे बनाये जाते हैं, गोल्ड के धागे वे चले गये सूरत में और वह बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दिये गये। नतीजा आज यह हो रहा है कि जो अरबों की साड़ी विदेशों में जाती है, हमारे हर घर में मां-बहिनें सुहाग के तौर पर पहनती हैं, उसी साड़ी का छह महीने के बाद जो धागे का रंग है, वह काला पड़ जाता है। अक्सर यह शिकायत आई है। इससे तमाम व्यापारी परेशान हैं। हम आपको बतलाएं कि हमको एक प्रतिनिधि मण्डल बनारस में मिला था कि तमाम विदेशों की कम्पनियों ने चिट्ठियां लिखी है कि हम अब हिन्दुस्तान से साड़ी नही मंगवाऐंगे। अब यही साड़ी वे पाकिस्तान से मंगवाऐंगे।

बनारस एक सांस्कृतिक नगर है। वहां नागरिक केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं जाते बल्कि विदेशी भी पर्यटन के लिये वहां आते है और वहां से साड़ी खरीद कर ले जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूगा कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि जो सूरत में नकली धागे बनते है वह बन्द करके असली धागे बनाने की इजाजत और लायसेन्स बनारस के छोटे-छोटे व्यापारियों को देंगे? दूसरा सवाल . . .

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव): आप एक प्रश्न कह समाप्त करें।

श्री रामेश्वर सिंह: मैं भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह सोडा के विषय में है जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है गाव में। हमको जो मालूम हुआ है. . .

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव): कृपया स्थान ग्रहण करें। यह बात नियम के खिलाफ है। वह प्रश्न दूसरे विषय में हैं।

श्री रामेश्वर सिंह: एक सैकेन्ड दे दीजिये। यह सोडा जो हैं उसमें नमक पीस करके तथा मिलावट करके डेढ़ रुपया किलों बाजरा में बिक रहा है। क्या मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे?

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव): इस विषय से सम्बन्धित आपकी बात नही है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज: उपसभाध्यक्ष जी, कई सवाल उठाए गए है। कुछ, कहां क्या बिक रहा है, वहां से लेकर मोटी नीतियों तक। जो विशेष सवाल उठाये हैं किसी एक उद्योग को लेकर, या किसी एक मामले को लेकर उनकी जानकारी हमको हासिल करनी पड़ेगी, जैसे बनारस मे असली धागे बनाने का काम से लेकर कौन कंपनी विशेष को क्या 7.00 P.M. लाइसेंस दिया है। मगर कुछ मोटी बातें जो यहां पर छेड़ी गयी हैं उनकी जहां तक हो सके मैं सफाई करना चाहूंगा। हालांकि पिछले दिसम्बर, में जो उद्योग नीति हम ने सदन के सामने रखी थी उसी में काफी स्पष्टतौर पर हम ने अपनी नीति को रखने का प्रयास किया था।

पहला सवाल है विदेशी कंपनियों का। मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि विदेशी कंपनियों को हम ने हिन्दुस्तान में नहीं बुलाया। दरअसल पिछले वर्ष दो सव से नामी विदेशी कंपनियों को इस देश से निकालने का काम हम ने किया और दो तीन ऐसी भी छोटी कंपनियां जिन के बारे मे हम को निर्णय लेने की जरुरत पड़ी तो हम ने उन के बारे मे निर्णय लेकर उन का हम ने संभवतः देशीकरण कर दिया। लेकिन विदेशी कंपनियों के बारे में हम ने कभी यह नही कहा कि हम उन को इस देश में रहने ही नहीं देंगे। वह विदेशी कंपनी

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

के रुप में या विदेशी पूंजी के रुप में यदि यहां हैं तो हम पहले दिन से ही यह कहते रहे सरकार में आने के पहले दिन से ही कि इस देश के हित में जो भी हम को नजर आयेगा उस को हम स्वीकार करेंगे और इस देश का अहित अगर किसी चीज मे हम को दिखाई देगा तो उन को हम बंद करेंगे या जो भी रोक और बंधन लगाना होगा वह हम उन पर लगायेंगे । तो जो हमारी नीति है वह बहुत स्पष्ट है । वह है कि देश के हित में हो, किसी भी क्षेत्र में विदेशी पूंजी को रखना या विदेशी कंपनी को काम करने देना और अगर वह हमारे नियम के कानून के अंतर्गत बैठने को तैयार हैं तो हम उन को रहने देंगे । और अगर वह हमारे कानून और बंधनों को अस्वीकार करते हैं तो हम उन को यहां रहने नहीं देंगे । वहां हित वाली बात भी सामने नहीं आयेगी । अब इस में कुछ बातें ठोस रूप से छेड़ी गयी । जैसे यह कहा गया कि अखबार में कोई ऐसी खबर छपी कि जो हमारी आई बी पी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उस के बजाय हम ने किसी विदेशी कंपनी यूनियन कारबाइड को लाइसेंस दे दिया । यह बात उपसभाध्यक्ष महोदय सरासर झूठ है । This is a damned lie that I have given a licence to a foreign company, Union Carbide, in preference to the I.B.P., a public sector undertaking. In fact, the contrary has happened. I have given the licence to IBP in preference to Union Carbide and this was done ten days ago.

अखबार में छपा । क्यों छपा यह मुझे नहीं मालूम । जैसे आज अखबार में यह भी छप गया कि जो इकोनामिक एफेयर्स की कमेटी की मीटिंग थी उस मे मैं हाजिर नहीं था और मैं उस समय महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बनाने के काम में लगा था जब कि मीटिंग बुलाने की शुरुआत से ले कर आखिर तक उस में मेरा काम था । मीटिंग मे जिन विषयों पर बहस हो, उद्योग मंत्रालय से जो मसविदा भेजा था उस पर निर्णय लेने का काम था, उस विषय में जो कुछ मुझे करना था वह मैं ने किया लेकिन अखबार में यह छपा कि The Industry Minister, Mr. George Fernandes was not present for the meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs. He was involved in or engaged in or concerned with the Ministry making exercises in Maharashtra.

मुझे उस से मतलब नहीं । लेकिन अखबार मे जो बात आयी है उस का मैंने खुलासा किया । चूंकि खुलासा करने की बात आती है इसलिये मैंने इस बात का खुलासा किया । अखबार में लिखने वाले अखबार वाले होते हैं । और अखबार में लिखने वालों को जरनलिस्ट कहते हैं । जिसने भी लिखा हो वह जरनलिस्ट होगा । अखबार का मालिक कौन है उस को छोड दीजिए । पूंजीपति लिखता नहीं है । लिखने का काम जरनलिस्ट करता है । तो इस लिये इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है । क्या कंपल्शन है । (*Interruptions*) फिर वही बात कर रहे हैं जैसी कल्पनाथ जी ने की बगैर जानकरी के ।

दूसरी बात यह छेड़ी गयी बी एच एल को लेकर, जिस में यह कहा गया कि--बंबई के एक अखबार में छपा है कि "बी एच एल बीग सोल्ड टु मल्टी नेशन्स" । और हमारे कल्प नाथ जी को याद आ रही है चिली की कि हम यहां उसी प्रकार की स्थिति को बनाने का काम तो नहीं कर रहे हैं और हालांकि मेरी नीयत पर उन को विश्वास है लेकिन षड्यंत्र ऐसा हुआ है कि जिस को लेकर बी एच एल जो हम लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र का एक शानदार उपक्रम है वह बिगड़ रहा है ।

SHRI KALP NATH RAI: That paper had written.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : यह उन की परेशानी है। मैं उन की परेशानी को समझता हूं। मैं किसी भी अखबार की न तो वकालत करूंगा और न उस का खंडन करूंगा। मुझे तो समाचार से मतलब है और उस का लिखने वाला जरनलिस्ट होता है। अब सुनते यह हैं कि सीमेंस के मामले को लेकर हम बी एच एल को बेच रहे हैं। बी एच एल बींग सोल्ड और मुझे खुशी है कि कल्प नाथ राय जी ने इस बात को छोड़ा है और उन को बहुत जानकारी है। उन्होंने कहा है कि उन को चिली का ख्याल आ रहा है। मैं विशेष रूप से इस मसले की जांच करूंगा क्योंकि यह 1976 का समझौता है। यह जो बहस हो रही है This is 1976 agreement and if my friend Kalp Nath Rai sees Chile in this...

श्री सीताराम केसरी : इस का मतलब यह हुआ कि जो पूर्व की सरकार ने किया उस का आप ने समर्थन किया। एक ओर तो आप उस का खण्डन करते हैं और दूसरी ओर आप उस का समर्थन करते हैं।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैं न किसी का खंडन कर रहा हूं और न समर्थन कर रहा हूं। मैं तो इस देश का भला चाहता हूं। मुझे इस से ज्यादा कुछ कहना नहीं है और बी एच एल के बारे में जितना और किसी को गर्व है उतना ही मुझे भी है और उस बी एच एल ने जो सीमेंस इंजीनियरिंग के साथ समझौता किया जिसके ऊपर अब आइन्दा मुहर लगाने का वक्त आ गया अगर उस के अंदर श्री कल्प नाथ राय और उन के साथियों को चिली से ले कर देश को बेचने तक की बातें दिखाई देती हैं तो मैं जरूर इस में और गहराई में जाने का प्रयास करूंगा। चूंकि 1976 का मामला है, वह जो तानाशाही के दिन थे उन दिनों का, तो मैं उस पर जरूर नजर डालूंगा...

एक माननीय सदस्य : जल्दी करिये।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : जल्दी करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : भाषा जल्दी समाप्त करिये।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : यह सब चीजें जल्दी करूंगा। तो इस लिये जो परेशानी है आप को वह मेरी वजह से बढ़ने नहीं पायेगी। मगर आप ने यह भी एक बुनियादी सवाल छेड़ा कि क्या पब्लिक सेक्टर को हम आगे चलने दे रहे हैं या यह सारा बड़े उद्योगपति और जो मल्टी नेशनल्स हैं उन को ले कर, उन को यहां ला कर इस पब्लिक सेक्टर का सफाया करने की बात हम करने जा रहे हैं। तो मैं सदन को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति पब्लिक सेक्टर को और मजबूत करने की है। किसी भी तरह से पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने की नीति नहीं है। हम कई और नये सेक्टर्स में इस पब्लिक सेक्टर को मजबूत करेंगे। जैसे हम एन टी सी की बात कर रहे हैं। हम एन टी सी को इस राष्ट्र के गरीब इंसान का सहारा बनाना चाहते हैं। वह जो कपड़ा पहनता है उस को वह कपड़ा पहुंचाने का काम हम इस के माध्यम से हो इस का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक तरफ हम हाथ करघा के इस्तेमाल की बात करते हैं उस के साथ अधिक काम निर्माण करने का सवाल जुड़ा हुआ है। उसी तरह से एन टी सी की जो शक्ति है वह इस देश के गरीब को कपड़ा पहुंचाने के काम में लगे और वह काम इस संस्था के माध्यम से हो इस काम में हम अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं। और कई क्षेत्रों में जैसे यह जो बस्ती है, लैंप्स उस में हम ने कदम उठाये हैं। हंगरी के साथ एक समझौता किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की कंपनी है लैम्प्स बनाने वाली टुंगसराम उस का एच एम टी के साथ समझौता किया गया, उस को एक साथ जोड़ने का काम किया। इस के चलते जो नये उद्योग देश में हम अभी बड़े पैमाने पर चलायेंगे उस काम की शुरूआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक अरसे से एक ही

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

बड़ी मल्टी-नेशनल कंपनी को इस क्षेत्र में पूरा मैदान खुला रखने का काम वर्षों से हुआ था, न सिर्फ हम उस पर रोक लगाने का काम करेंगे बल्कि देश में और विदेश में हम एच० एम० टी० और तुन्सराम का अपना हैसियत बनाने के लिए और विकास करने के लिए आगे ले जायेंगे ।

उसी तरह से देश में पिछले साल की बात है, हमें घड़ियों की आवश्यकता थी--60 लाख की । घड़ियां यहां बन रही थीं मुश्किल से 20 लाख । विदेश से आयात बन्द और सारा रास्ता खुला रखा था तस्करों का । प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सेक्टर अपनी जगह पर और तस्करों के लिए रास्ता सारा खुला रखा था । हमने पिछले साल एच० एम० टी० की और से जिस कंपनी के साथ कोलेबोरेशन है वहां से हमने 20 लाख घड़ियां अपनी तरफ़ से मंगा लीं पब्लिक सैक्टर में ताकि तस्करों का जो क्षेत्र एक अरसे से बना रखा था उसको हम तोड़ सके और उसको तोड़ा और एच० एम० टी० के विकास का ऐसा ढांचा बना दिया । टुंकूर में कारखाना बन रहा है जो अगले साल सितम्बर में काम शुरू करेगा जिसमें 20 लाख घड़ियां बननी शुरू होंगी ।

श्री सीताराम केसरी : निर्माण हुआ तो हमारा नहीं आपका हुआ, किसका हुआ ?

श्री जार्ज फर्नेंडीज : निर्माण तो न आपका हुआ, न हमारा हुआ, इस राष्ट्र का हुआ ।

श्री सीताराम केसरी : यह सब किसने किया ? 20 लाख घड़ियां बनेंगी आपकी मेहरबानी से कि पूर्व सरकार कांग्रेस की सत्ता में ये चीज़ें उपलब्ध हुई ? आपकी नहीं । आप सारी खामियों को पूर्व की सरकार पर थोपकर निकल जाना चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : जिस सदन में आप बहस कर रहे हैं, खड़े होकर बोल रहे हैं, इस सदन का निर्माता है अंग्रेज़ तो आप अंग्रेज़ी की तारीफ़ करेंगे ? कैसी बातें कर रहे हैं । . . . (*Interruptions*)

श्री सीताराम केसरी : श्रीमन्, यह गलत बात है । . . . (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : यह सदन अंग्रेज़ों ने बनाया, रेलें अंग्रेज़ों ने बनाई । . . . (*Interruptions*)

SHRI DEVINDRA NATH DWIVEDI: Please do not politicalise your speech.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : हम कहां पोलिटिकलाइज कर रहे हैं । हम तो एच० एम० टी० की घड़ियों की बात बता रहे थे । . . . (*Interruptions*)

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : इससे सस्ता जवाब श्रीमन् और क्या हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने सब कुछ किया है . . . (*Interruptions*) इसमें राजनीति क्यों लाते हैं?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : आप राजनीति क्यों लाते हैं ? राजनीति लाने का आपका अधिकार है तो हम नहीं ला सकते हैं ? . . .

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SHYAM LAL YADAV): Order please. Let the hon. Minister reply. Order, order please. (*Interruptions*) Mr. Minister, please conclude.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : यह बात कह रहे थे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनको जनता सरकार की तरफ से कमजोर करने की बात हो रही है । मेरा यह निवेदन है कि इसमें तथ्य नहीं है । हम तो सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं । इसी के संदर्भ में मैंने एच० एम० टी० घड़ियों का जिक्र किया । इस क्षेत्र में कंज्यूमर आइटम्स की बात भी चली तो मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास हो रहा है । आज तक जहां

हमारा देश जा नहीं रहा था ऐसे क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र को लाया जाए इस ओर भी हमारा प्रयास हो रहा है। कंज्यूमर्स गुड्स के बीच क्षेत्र में हम सार्वजनिक क्षेत्र को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये इस मसले पर सदन को चिंता नही करनी चाहिये और सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य के बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

अब सवाल यह है कि छोटे उद्योगों के लिये सुरक्षित रखे गये जो भी क्षेत्र हैं क्या हम वहां पर बड़ी और विदेशी कंपनियों को आने दे रहे हैं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 807 आइटम्स आज हमने छोटे उद्योगों के लिये सुरक्षित रखे हैं। इन सुरक्षित क्षेत्रों में हम किसी भी बड़ी विदेशी या देशी कंपनी को इसके आगे जाने नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि एक अर्से से जो कैपिसिटी बनी बनाई है उसका क्या किया जाए? कोई हम से कहे कि एक दिन में उसे करना है तो यह संभव नही होगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल दिसम्बर महीने तक जहां 187 आइटम्स रिजर्व थे वहां पिछले दिसम्बर महीने से अब तक 807 आइटम्स रिजर्व किये है। इन क्षेत्रों में हम जहां बड़े हैं वहां इन बड़ों को कैसे फेज आउट किया जाए इस दिशा में हमारे कदम बढ़े हैं और इस तरह से हम मानकर चलते है कि छोटे उद्योगों को विशेष संरक्षण देने के काम में काफी मदद मिलेगी।

श्री कुलकर्णी जी ने सवाल पूछा कानूनी संरक्षण के बारे में।

एक माननीय सदस्य : वह तो यहां पर नहीं है।

श्री जार्ज फर्नेंडीज : वह हम से बोल कर गये है।

मैं बताना चाहता हूं कि कानूनी संरक्षण के बारे में हम अगले ही सत्र में विधेयक ला रहे हैं। जिसके चलते छोटों को और इसके साथ-साथ जो कोटेज इंडस्ट्री है, दोनों को विशेष किस्म का संरक्षण देने का काम होगा। जो काम पिछले 10 वर्षों से नही हो रहा था वह हमारी सरकार की तरफ से किया जाएगा।

उन्होंने एक और शिकायत की कि जो पहले एक मंच रहा करता था जहां छोटे और दूसरे अपने बातों को, अपनी शिकायतों को जा कर वह कह सकते थे वह आजकल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पुनर्निर्माण करने में थोडा विलम्ब जरूर हुआ मगर हम उसे बना रहे हैं। करीब-करीब वह पूरा हो चुका है और अगले कुछ ही दिनों में छोटे उद्योगों को लेकर जिस मंच की आवश्यकता है, डैव्लपमेंट कौंसिल की, उसका हम एलान करेंगे और जो माननीय सदस्य की मंच के बारे में शिकायत है वह दूर हो सकेगी।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि कालगेट को मैंथल का लाइसेंस दिया। यह सही है, शत-प्रतिशत जो बटवारा है वह निर्यात करने की शर्त पर है और इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरी जो [illegible] की शिकायतें उठाई गई हैं अगर मेरे पास जानकारी होती तो मैं दे देता लेकिन जितनी मेरे पास जानकारी है उतनी जानकारी मैं दे रहा हूं। जो जानकारी मेरे पास नहीं है वह जानकारी भी मैं बाद में दे दूंगा। हमारे मित्र श्री झा ने एक वकील की भांति कुछ ठोस सवाल पूछे है। उन्होंने "क्या यह सही नहीं है कि" इस प्रकार से सात आठ सवाल पूछे हैं। उनके संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सही है कि बहुत पहले से ही हमारे देश में ये औद्योगिक घराने बढ़ते रहे है और बढ़ाये गये हैं। किन किन लोगों के साथ क्या क्या संबंध या रिश्ते बनाये गये, यह भी सब को मालूम है। कुछ

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

लोगों के द्वारा हमारे देश में इस औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहन देने का काम भी हुआ है । ये सब बातें सही हैं । यह बात सही है कि इस देश की अर्थ व्यवस्था पर 20 घरानों का कब्जा रहा है । पिछले वर्षों में इन घरानों को ही बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है । ऐसी स्थिति में कोई हम से यह आशा करे कि हम एक क्षण में इन नीतियों को बदल देंगे, यह संभव नहीं है । पुराने ांचे को एकदम से हम बदल सकें, यह संभव नहीं है । मैं इस बात को पहले भी स्वीकार कर चुका हूं कि इस ढांचे को एक क्षण मे समाप्त करना संभव नही है । यह काम हमारी सरकार के लिए या किसी अन्य के लिए भी संभव नहीं है । देश के अन्दर सौ वर्षो से बना हुआ ढांचा, और पिछले 30 वर्षों में बनाया गया औद्योगिक ांचा एकदम से समाप्त कर दिया जाय, यह किसी प्रकार से भी संभव नहीं है । हमने इस सदन में अनेक बार कहा है कि हम संविधान की मर्यादाओं को मान कर काम कर रहे हैं। हम नियमों और संविधान को आधार मान कर काम कर रहे हैं ।

SHRI KALP NATH RAI: You can't do it.

श्री जार्ज फर्नेंडीज: : आप जरूर कह सकते हैं कि You can't do it क्योंकि आपका इससे विरोध है । आपने इस ढांचे को इसलिए नहीं बनाया था कि कोई आकर इसको तोड़ेगा । इसीलिए आप इस प्रकार की बातें कह रहे हैं । मैं मानता हूं कि आप लोग उन्ही घरानों की ओर से बोल रहे हैं । इन घरानों को तोड़ना पसन्द नहीं करते हैं

श्री सीताराम केसरी : : हम एकदम से इनको तोड़ना पसन्द करते हैं । आप इस प्रकार की बात मत कहिये ।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि.... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Order please. Let him conclude first. If anything remains... (*Interruptions*)

SHRI YOGINDRA MAKWANA: What about this letter written by Shri Remeshwar Singh? (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नेंडीज : : माननीय सदस्य जिस लेटर का जिक्र कर रहे है, उसका मुझे पता नहीं है । यह लेटर मैंने देखा नही है । अगर वे मुझे लेटर दे दें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन, मुझे यह निवेदन करना है कि....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Kindly resume your seat. Let him complete. You have already spoken. Let him conclude. आप बैठ जाइये, पहले उनका उत्तर सुन लीजिये ।

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैने कुछ बुनियादी सवाल उठाये है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : पहले उत्तर सुन लीजिये ।

HRSI KALP NATH RAI: Sir, I am making a request that you must...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Unless you let him complete his answer, how can you say that he has not replied? Let him complete his answer.

SHRI KALP NATH RAI: HE must speak about the Industrial Policy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Let him omplete his answer.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो 30 वर्षों में बनाया गया ढाचा है यदि कोई एकाएक यह अपेक्षा रखता है कि उसे तोड़ दिया जाये यह सम्भव नहीं है और इसमें सिर्फ जनता सरकार, जनता सरकार कहकर इससे कुछ बात बन नहीं रही है। आपने जिकर किया कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का कि उसकी अर्जी है और उसको न देते हुए आप किसी और को देख रहे हैं किसी बड़े को देख रहे हैं। कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने कोलाबरेशन की मांग की है, किसके साथ? विलकिन्सन के साथ। एक और मल्टीनेशनल अब लोग आ रहे हैं हमारे पास। कर्नाटक सरकार इस बात को लेकर आ रही है, कर्नाटक के उद्योग मंत्री हम से कह रहे हैं कि आप इस विदेशी कम्पनी विलकिन्सन और कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन इन दोनों की सांठगांठ करके इनको एक नया लाइसेंस देने का काम करें। जब इस मामले पर निर्णय लेने का वक्त आ जायेगा तब हम इस पर उचित निर्णय ले लेंगे।

श्री सीताराम केसरी : आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है और शीपयेज को आपने अप्रूवल दिया है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है।

श्री सीताराम केसरी : यह गलत बात है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : यदि यह गलत बात है तो...

श्री सीतारम केसरी : आपने इसका जवाब अभी तक नही दिया कि... *(Interruptions)*

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उपसभाध्यक्ष जी, सदन के कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार मुझे सजा दी जा सकती है अगर इस सदन के सामने कोई गलत बात कहूं। इस सदन के नियम हैं, उसके लिये चिल्लाकर क्या मिलेगा। उसके लिये नियम के अनुसार हमारे ऊपर चार्ज लाइये।

श्री सीताराम केसरी : आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 10 मई को आपने जो उत्तर दिया था उसके संदर्भ में कल्पनाथ राय जी ने जो क्वेशन दिया था उसका उत्तर क्यों नही दे रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : उसभाध्यक्ष जी, अगर 10 मई को इस सदन में कोई जवाब दिया गया और उस जवाब को लेकर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो उस शिकायत को लेकर, अगर उसमें काम गलत हुआ है, सदन को किसी गलत दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है तो उसके लिये कुछ नियम हैं, उसके लिये नियमों का इलाज है, उसके लिये इस तरह से गुस्सा करके कुछ निकल आना नहीं है। इलाज है तो उस इलाज के अनुसार आप लोग आगे बढ़िये, नियम के अनुसार आप आगे बढ़िये। *(Interruptions)*

कर्नाटक की हमारे सामने अर्जी आती है कि मल्टीनेशनल को हम ले आयें और उसके साथ मिलकर हम कोई भी काम करें। जैसे एक तरफ कर्नाटक हमारे पास ऐसी अर्जी करेगा वैसे ही दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से आती है अर्जी। पश्चिमी बंगाल बिजली का काम, कलकत्ता, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, 100 प्रतिशत स्ट्रलिग कंपनीज, लंदन में जिसका रजिस्टर्ड आफिस है, जिसका हिसाब किताब रुपयों में नही बल्कि पौंड स्ट्रलिग में रखा जाता है उसको देना चाहती है। कामरेड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वहां के मुख्य मंत्री ने न सिर्फ उनको लाइसेंस देने की बात की बल्कि जब उसको पूंजी की कमी महसूस हुई, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के लंदन स्थिति लोगों ने कहा

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

कि पूंजी की कमी है और अगर आप पूंजी का इन्तजाम करें तो तब ही हम इसके विकास करने का काम करेंगे, तो यहां तक कि उन्होंने उनके लिये पूंजी जुटाने का काम किया । फिलिप्स इन्टरनेशनल एक और मल्टीनेशनल पश्चिमी बंगाल में काम कर रहा था । फिलिप्स इन्टरनेशनल का काम वहां पर बन्द होने को आ गया तो पश्चिम बंगाल की सरकार हमारे पास आई और बोली कि इसको बन्द मत होने दीजिये । फिलिप्स इन्टरनेशनल का जो कारखाना था उसमें कोई सैकड़ों लोगों को काम मिलता था और वे जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे वह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था । इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार और फिलिप्स इन्टरनेशनल हम दोनों मिलकर, संयुक्त कम्पनी बनाकर उद्योग चलायेंगे । हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हमको मंजूर है । हमने स्वीकार किया ।

टाटा को पावर प्रोजेक्ट देने की बात आई । मैं महाराष्ट्र के उस समय के मुख्य मंत्री बसंत दादा पाटील के पास गया । उस समय दोनों एक ही कांग्रेस थी, दो भी नही थी । हमने उस सरकार के मुख्य मंत्री से कहा कि देखिये बम्बई में बिजली की कमी है, एक हजार मेगावाट बिजली की कमी है । तीन चार वर्षों से टाटा की अर्जी पड़ी है । इस पर अभी केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय नही दिया । बिजली की कमी के चलते लाखों लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है । एक हजार मेगावाट बिजली का मतलब है एक हजार करोड़ रुपये का उत्पादन । इसके न होने से करोड़ों रुपये के उत्पादन का नुकसान हो रहा है तो आप इस बिजली घर को बना दीजिए । वे हम से बोले कि यह हमारे बस का नहीं है । आप टाटा को दे दीजिये । हमने कहा कि हम टाटा को दे देंगे और हमने दे दिया । मैंने शुरू से कहा कि इस देश में जो कमियां पिछले एक जमाने से निर्माण हुई हैं आर्थिक क्षेत्र में अभी जिसकी ओर हमारे मित्र रघुनाथ रेड्डी जी ने इशारा किया । जब उन्होंने कहा "economics of anti-growth' इस देश में जो बनी हुई है "the economy of shortages" यह जो हमारे ऊपर एक जमाने से आ गई उसमें से देश को बाहर लाना है और उस में से देश को बाहर लाते समय इस देश के विकास को मद्देनज़र रखते हुए जो नीतियां हमको बनानी पड़ेगी वह हम अपनाएंगे और वह नीति अपने देश में...

श्री योगेन्द्र मकवाणा : सदन को बम्बई की चौपाटी समझकर भाषण कर रहे हैं..

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : हम तो संसद् को बम्बई की चौपाटी नहीं समझते । आपको चौपाटी और संसद् में कोई फर्क नहीं दिखता । हम बम्बई की चौपाटी के गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं । हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं । हो सकता है आप गोंदिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले है और हम चौपाटी की सड़क के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं । कुछ फिक्र मत कीजिये । उपसभाध्यक्ष महोदय, देश हित को मद्दे नजर रखते हुए जिस क्षेत्र में निर्णय हम को लेना है वह निर्णय हमने लिए हैं । सारी हमारी जो नीति है वह 23 दिसम्बर को इस सदन में पेश की गई । उसके बाहर जा कर कोई कदम हमने नही उठाया है और न ही उठाया जाएगा । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at thirty-two minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 2nd August, 1978.